

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराज): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) यह डाक-टिकट मद्रास के मुख्य मंत्री की प्रार्थना पर जारी किया गया था। इसमें सम्मेलन के 'एम्ब्लेम' का ठीक वैसा ही चित्र दिया गया है जैसा कि उन्होंने भेजा था।

LOW PRICE OF FOODGRAINS IN PUNJAB AND HARYANA

*61. SHRI N. K. P. SALVE:
SHRI YAJNA DATT SHARMA:
SHRI Y. S. KUSHWAH:

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the stocks of foodgrains particularly of wheat far exceeded the demand in the markets in the States of Haryana and Punjab and are selling at extra-ordinarily low prices;

(b) whether the same commodity is selling at very high prices in the neighbouring States of Delhi and U.P.; and

(c) if so, whether Government propose to readjust the Food Zones in the light of these circumstances?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE):

(a) Punjab and Haryana being surplus States, the availability of foodgrains generally exceeds the local demand. The prices of foodgrains including wheat have fallen since October, 1967 in the States of Haryana and Punjab. The falling trend in prices is because of a good *khari* crop in the case of *khari* cereals and expectation of a good *rabi* crop in the case of

the State Government, Co-operatives and the F.C.I. make purchases of foodgrains at the procurement prices to ensure that the prices do not fall below the level of the procurement prices.

(b) The prices of wheat in Delhi and U.P. are somewhat higher than in Haryana and Punjab. There is always some difference in prices between the surplus and deficit States.

(c) The matter of zonal restrictions will be considered as usual in the next meeting of the Chief Ministers called to consider *Rabi* Policy.

आयातित गेहूँ तथा माइलो के मूल्यों में वृद्धि

*71. श्री मधु लिमये : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक सभा के शीतकालीन सत्र के स्थगित होने के पश्चात् सरकार ने अमरीका से आयात किये गये गेहूँ और माइलो के विक्रय मूल्य बढ़ा दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रति किलो बिक्री मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) किन-किन राज्यों ने इस वृद्धि के खिलाफ केन्द्रीय सरकार को लिखा है; और

(घ) गेहूँ के मूल्य में उक्त वृद्धि के परिणामस्वरूप अन्य खाद्यान्नों के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां। केन्द्रीय भंडार से सप्लाई किए जाने वाले आयातित गेहूँ तथा माइलो के निर्गम मूल्य पहली जनवरी, 1968 से बढ़ा दिये गये हैं।

(ख) आयातित गेहूँ तथा माइलो के निर्गम में क्रमशः 12 पैसे और 8 पैसे प्रति